

एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है, आमजन को परेशानी नहीं होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने एलपीजी सप्लाई की समीक्षा की तथा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग कर्मियों के अवकाश निरस्त किए

जयपुर, 11 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु तथा सामान्य है। इसकी आपूर्ति को

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर व संबंधित अधिकारियों को निरन्तर मॉनिटरिंग के निर्देश दिये ताकि आम उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और एलपीजी गैस व पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो पाये।**

लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में निर्देश दिए एलपीजी गैस आपूर्ति को निर्बाध



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को एलपीजी गैस आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए।

बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं। उन्होंने नागरिक आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मिकों के अवकाश निरस्त किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम

उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे मामले के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर निरंतर

मॉनिटरिंग करें। शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारेगी

नई दिल्ली, 11 मार्च। पश्चिम एशिया में गहराते संकट और ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के बीच, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। आपूर्ति बाधित होने की बढ़ती

■ **एजेंसी के सभी 32 सदस्य देशों ने ईरान वॉर के मद्देनजर सर्वसम्मति से यह फैसला किया**

आशंकाओं के मद्देनजर, आईईए के सभी 32 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अपने आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है।

यह ऐतिहासिक फैसला आईईए के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। इससे पहले 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण स्तर का आक्रमण किया था, तब एजेंसी के सदस्य देशों ने बाजार में 18.2 करोड़ बैरल तेल उतारा था। वर्तमान फैसला पिछले रिकॉर्ड के दोगुने से भी अधिक है।

घरेलू एलपीजी की आपूर्ति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) (एल.एन.जी.) और पाइप नैचुरल गैस (पीएनजी) की उपरती कमी यह दिखाती है कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था आसम में कितनी जुड़ी हुई है। एलएनजी की कमी का असर पहले ही उर्वरक कारखानों पर पड़ रहा है, जिससे कुछ इकाइयों को उत्पादन कम करना पड़ रहा है और आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। इसका असर केवल खाद्य सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि उर्वरक सप्लाई पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही सरकार के बजट की सबसे बड़ी मर्दा में से एक है। गैस आपूर्ति में शुरू हुई बाधा जल्दी ही कृषि, महंगाई और सरकारी विच पर असर डाल सकती है।

तोसरा, घरेलू उपभोक्ताओं को

प्रार्थमिकता देने के सरकार के फैसले का असर कमर्शियल उपभोक्ताओं, जैसे रेस्तरां, होटल और छोटे खाद्य कारोबार, पर पड़ना तय है। घरेलू खपत की रक्षा करना एक तार्किक नीति है, लेकिन अगर कमर्शियल एलपीजी की कमी लंबे समय तक रहती है तो इससे खासकर छोटे प्रतिष्ठानों को नुकसान हो सकता है, जो बहुत कम मुनाफे पर काम करते हैं। इसलिए नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रार्थमिकता अस्थायी रहे और आपूर्ति में लंबे समय का असंतुलन न पैदा करे।

अंत में, यह घटना पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक झटकों के प्रति भारत की लगातार बनी हुई संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। एशिया की सबसे

बड़ी रिफाइनिंग व्यवस्थाओं में से एक होने और आयात के विविध स्रोत होने के बावजूद देश अभी भी बाहरी ऊर्जा आपूर्ति पर काफी निर्भर है। बार-बार आने वाले संकट, चाहे तेल के झटके हों या गैस की कमी, यह सिखाते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक प्रार्थमिकता के रूप में देखा होगा। सरकार के तेज हस्तक्षेप से फिलहाल स्थिति को स्थिर करने में मदद मिली है। लेकिन जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर बने हुए है, तब असली चुनौती केवल मौजूदा संकट को संभालने की नहीं, बल्कि एक अधिक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था बनाने की है।

दूर सुरक्षित है।

दूसरी ओर, अपने अहम को भुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के तेल के अधिक प्रवाह को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने यह घोषित किया कि उसने भारत को रूस का तेल खरीदने को अनुमति दी है, जिसे बाद में भारत ने नकारा।

संकेतों के अनुसार, यूरोपीय देशों की भी रूस का तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, अगर कुछ भी नहीं तो वैश्विक तेल बाजार की शांति देने के लिए। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की है।

राष्ट्रपति ट्रम्प के दावों को खारिज करते हुए, भारत ने अपनी संप्रभु अधिकार को दोहराया कि वह तेल और किसी अन्य चीज को अपनी समझ और स्वतंत्रता से खरीदेगा, न कि अमेरिका की छूट पर निर्भर होगा।

इस प्रकार संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ अपने महंगे युद्ध को समाप्त करने के विकल्प की तलाश में है और ईरान अमेरिकी संपत्तियों और उसके सहयोगियों पर अपने आक्रोशित हमलों को जारी रखने की धमकी दे रहा है।

भारत ने रूस से 3 करोड़ बैरल कूड ऑइल खरीदा

नई दिल्ली, 11 मार्च। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। विशेष रूप से होरमुज जलडमरूमध्य के बंद होने जैसी स्थिति ने कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ा दिया है। यही कारण है कि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख किया है।

जानकारी के अनुसार, भारत की रिफाइनरियों ने रूस से लगभग 30 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की खरीद की है।

यह खरीद ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिका ने भारत को इस संबंध में अस्थायी छूट प्रदान की है, ताकि वह पश्चिम एशिया से कम हुई आपूर्ति की भरपाई कर सके।

पिछले साल भारत ने अमेरिका के दबाव के चलते रूस से तेल खरीद में कमी करना शुरू कर दिया था। उस समय भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाया था।

राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह 19 मार्च को जालोर में होगा

मुख्यमंत्री भजनलाल 15 को जयपुर में "विकसित राजस्थान रन" का फ्लैग ऑफ करेंगे

जयपुर, 11 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गत वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाते की शुरुआत की गई। इसी क्रम में इस बार भी राज्य सरकार प्रदेशभर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (19 मार्च) को राजस्थान दिवस मनाया जा रही है। प्रदेशभर में 14 मार्च से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जो 19 मार्च तक आयोजित होंगे।

आयोजन की शुरुआत 14 मार्च से सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ होगी। 15 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय 'विकसित राजस्थान रन' का आयोजन होगा जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। 15 मार्च को ही 'राजस्थान को

■ **राजस्थान दिवस समारोह के तहत 16 मार्च को इंद्रपुर के बेणेश्वर धाम में "राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस" का आयोजन होगा तथा 17 मार्च को जयपुर में "राजस्थान युवा शक्ति दिवस" आयोजित होगा।**

जानें' डिजिटल विजय का शुभारंभ तथा जयपुर में ओडीओपी मेला एवं प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया जाएगा। इसी दिन शाम को दिल्ली के बीकानेर हाउस में पांच दिवसीय 'राजस्थान दिवस/बीकानेर हाउस' का शुभारंभ किया जाएगा।

16 मार्च को इंद्रपुर के बेणेश्वर धाम में 'राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस' का आयोजन किया जाएगा। 17 मार्च को जयपुर में 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' मनाते हुए राज्य स्तरीय

युवा सम्मेलन का आयोजन होगा। 18 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया जाएगा। शाम को प्रदेशभर में राजकीय मंदिरों में आरती का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री भी महाआरती में शामिल होंगे।

राजस्थान दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन 19 मार्च को जालोर में किया जाएगा। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन आयोजित होगा। शाम को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षा के हाईटैक नकल गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

■ **एसओजी, गिरोह के अन्य सदस्यों व उपभोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है।**

दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर षड्यंत्रपूर्वक परीक्षा दिलाई गई थी। जांच में पहले मूल अभ्यर्थी इंद्रराज सिंह, सहयोगी आरोपी परमेश्वर लाल और सलमान खान को गिरफ्तार कर चालान पेश किया जा चुका है। वहीं डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास निवासी हिसार (हरियाणा) को 27 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

जांच में सामने आया कि गुरदीप

दास परीक्षा केन्द्र में विशेष स्मार्ट डिवाइस लेकर प्रवेश करता था और प्रश्नपत्र को फोटो लेकर बाहर भेज देता था। बाहर मौजूद अजीत कुमार इंटरनेट और अन्य विशेषज्ञों की मदद से प्रश्न हल कर वापस भेजता था, जिससे डमी परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हो जाता था। मामलों की जांच एसओजी के उपमहानिरीक्षक परिस देशमुख के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह द्वारा की जा रही है। एसओजी गिरोह के अन्य सदस्यों और उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संबंध में भी जांच कर रही है।

इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 1 मूल अभ्यर्थी, 1 डमी परीक्षार्थी, 2 मध्यस्थ और 1 सहयोगी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की इजाजत दी

12 वर्षों से कोमा में चल रहे 32 वर्षीय युवक के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी

■ **वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉमन कॉज के मामले में इच्छा मृत्यु को मान्यता देने का फैसला किया था, पर अब तक कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया था।**

ऐतिहासिक है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर भारत में परोक्ष इच्छामृत्यु (पैसिव यूथनाशिया) का यह पहला मामला है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2018 में कॉमन कॉज के मामले में परोक्ष इच्छामृत्यु को मान्यता का फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि कोमा जैसी स्थिति में पहुंचे रोगी की जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में विशेषज्ञ राय के लिए एक प्राथमिक और एक सैंक्रेडी

चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होगा और उसकी राय पर ही फैसले में तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक परोक्ष इच्छामृत्यु की इजाजत हो सकती है। इस फैसले के बावजूद, आज तक किसी भी मामले में इससे पहले कभी किसी को इसकी इजाजत नहीं मिली थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को दिए फैसले के केन्द्र सरकार से परोक्ष इच्छामृत्यु पर व्यापक कानून लाने पर विचार करने को भी कहा है। परोक्ष इच्छा मृत्यु किसी

व्यक्ति की जीवन रक्षक प्रणाली हटाने और आवश्यक उपचार बंद करके उसे प्राकृतिक रूप से मरने देने की प्रक्रिया को कहते हैं। बुधवार को न्यायमूर्ति जेबी पाटीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने परोक्ष इच्छामृत्यु की इजाजत मांगने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए इच्छामृत्यु की इजाजत देने का यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जीवन रक्षक उपकरण हटाने की इजाजत देते हुए कहा, उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, यह सिर्फ दुख को बढ़ाएगा। यह मामला गाजियाबाद के हरीश राणा का है जो पंजाब विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्र थे और 2013 में अपने पेशेवा गेस्ट आवास की चौथी मंजिल गिर गए थे।

कांग्रेस प्रत्याशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लगाया था कि उपचुनाव के दौरान नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में, मल्लोत्रा ने अपने खिलाफ चले गए आपराधिक मामलों की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मल्लोत्रा ने अपने नामांकन के साथ दिए हलफनामे में चार आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। मामले में दलील

दे रहे अधिवक्ता एम पी एस रघुवंशी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कई बार यह निर्देश दे चुका है कि नामांकन भरते समय उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। अदालत ने पाया कि इस निवेदन का पालन नहीं किया गया और इसलिए मल्लोत्रा का चुनाव रद्द कर दिया गया।

स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सामान्य लोकना नहीं है। करीब चार दशक बाद घटकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

भारत में गहराया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है, जो अब तक नहीं देखा गया था, खासतौर से तब से, जब मध्य-पूर्व और यूक्रेन के संघर्ष क्षेत्रों विशेष रूप से क्योंकि मध्य-पूर्व और यूक्रेन के संघर्ष क्षेत्रों में भारत की 1.47 करोड़ की आबादी को खिलाने की क्षमता को इसी तरह से कमजोर किया गया है। यह रोजगार और आजीविका पर भी असर डालता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर बेहद निर्भर है।

ईरान ने ...

डेटा के अनुसार, युद्ध और होर्मुज्द पर अनौपचारिक नाकाबंदी के कारण भारत को उर्वरक सप्लाई चैन में 20-25 प्रतिशत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि तेल की तरह, खाड़ी क्षेत्र से, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और ओमान से, शिपमेंट होर्मुज्द जलडमरूमध्य के माध्यम से ही भेजे जाते हैं कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, यह कोई मामूली परेशानी नहीं है।

ईरान ने ...

चूंकि इस झूठ सरकार ने हमारे नेता की हत्या की है, इसलिए हमारा वर्ल्ड कप में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के इस फैसले से फीफा के लिए भी स्थिति खराब हो गई है। फीफा अध्यक्ष जियानो इन्फेन्टिनो ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वाइट हाउस में बैठक के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने परोसा दिलाया है कि ईरान की टीम का वर्ल्ड कप में स्वागत किया जाएगा।

विधानसभा चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते हैं। अब तक राहुल गांधी या उनके कार्यालय की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि यह चुप्पी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, खासकर तब जब यह आशंका जताई जा रही है कि यह घोटाला के विचार चुनाव को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस वहां लगातार दो हार के बाद फिर से सत्ता में

लौटने की उम्मीद कर रही है। भाजपा और वाम दल दोनों ही इन नेताओं के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। यह विजयी घोटाला अब केरल, हरियाणा और नई दिल्ली में चर्चा का विषय बन गया है। सुर्जों का कहना है कि इसी नेता से जुड़ा एक और मामला, जो एक महिला से संबंधित बताया जा रहा है, सामने आने वाला है और किसी भी समय बड़ा विवाद बन सकता है। संबंधित महिला भी हरियाणा की बताई जा रही है।

क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जहाजों की सुरक्षा करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कमी बनी रही। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजरायल के पास ईरान की तुलना में विशाल शक्ति है।

फिर भी, उस शक्ति असंतुलन के बावजूद, ईरान ने संयुक्त सेनाओं और उनके हमलों का मुकाबला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों के विपरीत, ईरानी शासन को ईरानी जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ है, जबकि ठीक एक महीने पहले तक यह शासन ईरानी लोगों की घृणा का पात्र था।

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे , कि ईरान का कोई भी नया नेता संयुक्त बलों द्वारा मारा जाएगा, के खिलाफ आईआरजीसी ने नए नेता के रूप में दिवंगत नेता खामनेई के बेटे का नाम लिया है। यह एक उल्लेख कदम था, जैसे उग्र सांड को लाल लाल कपड़ा दिखाना।

इसके अलावा, ईरान के आक्रमणों के कारण, पश्चिमी एशियाई खाड़ी की क्षेत्रीय शक्तियां भी परेशानी महसूस कर रही हैं और युद्ध से बाहर निकलने के तरीकों की तलाश कर रही हैं। ये देश युद्ध के मोर्चे पर हैं, जबकि अमेरिका आठ हजार मील

अमेरिका -इजरायल ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दिया है। इससे पहले तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आने लगी थी, लेकिन अन्य बाजारों में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं।

डॉनल्ड ट्रंप की दिलासा देने वाली बातों के बावजूद यह पता चला है कि अमेरिका होर्मुज्द स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर झूठी अफवाह फैला रहा था। दिन के समय यह दावा किया गया था कि एक सशस्त्र अमेरिकी जहाज पहले ही एक जहाज को स्ट्रेट से सुरक्षित पार करा चुका है, लेकिन बाद में वाइट हाउस ने औपचारिक रूप से इस दावे से इनकार कर दिया।

इससे स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि दावों और खंडनों से साफ हो गया कि अब तक अमेरिका होर्मुज्द स्ट्रेट पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो पाया है। इसके बाद उसने यह भी दावा किया कि अमेरिकी बलों ने इस पानी में ईरान के 16 बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को डुबो दिया है। हालांकि वह साफ है कि हमलों की तैयारी में ईरान

पहले ही स्ट्रेट में भारी मात्रा में सुरंगें बिछा चुका है। पश्चिम एशिया का यह युद्ध अब तेजी से तेल की कीमतों की लड़ाई में बदलता जा रहा है। जहाँ डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी तेल और गैस की कीमतें कम करने का वादा कर रहे हैं, वहीं वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और तेल खरीदने वाले देशों में डर का माहौल है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई और कल ही यह घटक 90-91 डॉलर प्रति बैरल तक आई थी।

लेकिन बुधवार के दिन फिर से इसमें तेज बढ़ोतरी देखी गई। इस बीच यूरोपीय सरकारें बाजार को शांत करने के लिए अपने स्ट्रेटिजिक ऑयल रिजर्व से तेल जारी करने पर सहमत हो गई हैं।

जी-7 और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने स्ट्रेटोजिक ऑयल रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़ने पर सहमति दी है, जो उनके कुल तेल भंडार का लगभग एक

तिहाई हिस्सा है। तथापि, इतने बड़े पैमाने पर तेल जारी करने के वादों के बावजूद बाजार शांत नहीं हुए हैं। गैस की स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि कतर के कुछ सबसे बड़े गैस क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है।

तेल बाजार स्ट्रेटोजिक ऑयल रिजर्व से तेल रिलीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ईरान ने उस संकरे मार्ग को बंद करने का पक्का इरादा कर लिया है, जिससे दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का आयातमान होता है। इससे तेल की कीमतों को स्थिर करने की सभी कोशिशों को बड़ा झटका लग रहा है।

होर्मुज्द स्ट्रेट को लेकर ईरान की भाषा और कार्रवाई दोनों ही ज्यादा आक्रामक होती जा रही हैं, जबकि अमेरिकी पक्ष जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित निकालने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है। इन दावों के बावजूद तेल और भ्रम को और बढ़ा दिया है।